बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 214 ● नई दिल्ली ● वीरवार 11 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जहांगीरपुरी में खड़ी बाइकों में लगी आग, तीन वाहन जलकर खाक; सीसीटीवी फुटेज से जांच

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में इन दिनों आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहांगीरपुरी में खड़ी दोपहिया गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसमें तीन वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीती आठ जून की रात को जहांगीर पुरी पुलिस स्टेशन को ई-ब्लॉक में खड़ी दोपहिया गाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली। इस घटना में तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें एक टीवीएस एक्टर, एक स्प्लेंडर प्लस और एक जुपिटर स्कूटर शामिल थे। गनीमत रही कि आगजनी में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

आशंका और बेचैनी से घिरे लाखों लोगों को राहत, यमुना डूब क्षेत्र की 92 कॉलोनियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली । यमुना ओ-जोन क्षेत्र (डूब क्षेत्र) में बसी कॉलोनियों और गांवों में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। ध्वस्तीकरण के अंदेशे के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओ-जोन में स्थित पुरानी आबादियों और पहले से बने निर्माणों पर किसी प्रकार की विध्वंस कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ओ-जोन क्षेत्र में लगभग 91-92 अनधिकृत कॉलोनियां और एक दर्जन पुराने गांव स्थित हैं, जहां करीब 15 लाख लोग निवास करते हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में लगाए गए सरकारी नोटिस बोर्डों की

वजह से लोगों में भ्रम और भय का माहौल है। बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और भाजपा संगठन इस विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। बिधूड़ी ने बताया कि संबंधित कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया गया था और उस समय वे एफ-जोन में आती थीं। बाद में 10 अगस्त 2010 को तत्कालीन केंद्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकारों ने इन क्षेत्रों को ओ-जोन में शामिल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2013 में डीडीए ने इन इलाकों को पुनः एफ-जोन में लाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था, लेकिन आज तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो सकी।

नए व चल रहे निर्माण पर है हाईकोर्ट को चिंता

हाईकोर्ट के आदेशों और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अदालत की चिंता नए और चल रहे निर्माणों को लेकर है, न कि वर्षों से बसी कॉलोनियों या पुराने निर्माणों को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर निवासियों को डराने के साथ-साथ अवैध निर्माण भी करवा रहे हैं।

स्पष्टीकरण मांगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीडीए अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि हाईकोर्ट ने पहले से बने निर्माणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत की ओर से उठाए गए सवाल मुख्य रूप से नए निर्माणों से जुड़े हैं इसलिए डीडीए को उसी भावना के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए।

कैबिनेट बैठक में गूंजी तालियां, पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर मंत्रियों ने खड़े होकर थपथपाई मेजें

नेशनल डेस्क । (वेबवार्ता) केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 10 जून, 2026 को भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया गया और देश के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी की तारीफ़ की गई। कैबिनेट सदस्यों ने इस ऐतिहासिक मील के पत्थर, उनकी सरकार के तहत उपलब्धियों के पैमाने और रेंज का जश्न मनाने के लिए देर तक मेजें थपथपाई और तालियां बजाईं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर सम्मान स्वीकार किया। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का एक वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय ने शेयर किया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह वायरल हो गया, जिसे कई लाइक और रिएक्शन मिले। वीडियो में, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री देखे जा सकते हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने लगातार तीन टर्म तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 4,399 दिनों तक सेवा करने का रिकॉर्ड बनाया और जवाहरलाल नेहरू का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक सेवा की थी। कैबिनेट प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देते हुए कहा गया, यह मौका भारत की लोकतांत्रिक सोच, जनता के भरोसे और जनता की भागीदारी की ताकत का प्रतीक है, जो राष्ट्र पहले के संकल्प से चलने वाले नेता को लोगों के अभूतपूर्व समर्थन को दिखाता है। इसमें यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल की सेवा के ऐतिहासिक पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं। संवेदनशीलता, संयम, इरादे और फैसले लेने की क्षमता वाली लीडरशिप पर गर्व करते हुए, ऑफिशियल टेक्स्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि छह दशकों के बाद देश ने हाल सरकार को लगातार तीसरे टर्म के लिए जनादेश दिया है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के जीवन को सेवा और राष्ट्र-निर्माण के लिए लगातार समर्पण का प्रतीक बताया गया और 2014 में प्रधान सेवक के तौर पर उनके ऐलान को याद किया गया, जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के लिए कमिटेड थे।इसमें माना गया कि गरीबों की भलाई को शासन के सेंटर में रखा गया है, और पक्के घर, बिजली, साफ पानी, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने के साथ-साथ 80 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मुफ्त राशन और 60 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को मुफ्त मेडिकल इलाज देने की जानकारी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि इन कोशिशों से मिलकर देश का आत्मविश्वास बढ़ा और 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी हराने में मदद मिली। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, यह प्रस्ताव खास डेमोग्राफिक्स के एम्पावरमेंट को और मैप करता है। यह युवा शक्ति पर फोकस को पहचानता है जिसने भारत को मिशन चंद्रयान के ज़रिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और एक साइंटिफिक पावर बनने में मदद की। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक नया चैप्टर स्मोक-फ्री किचन और लखपति दीदी कैंपेन से लेकर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 33 परसेंट रिज़र्वेशन तक, पूरी पॉलिसीज़ के ज़रिए डिटेल में बताया गया है। ससने किसानों को विकसित भारत का एक अहम पिलर बताया और PM किसान सम्मान निधि और चरवाहों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड देने जैसी पहलों की तारीफ़ की, जिनसे खेती के एक्सपोर्ट को 5 लाख करोड़ रुपये के पार ले जाने में मदद मिली है। इसने आर्टिकल 370 को हटाने, GST और OROP को लागू करने, CAA कानून, भारतीय न्याय संहिता और लेबर कोड को एक साथ लाने जैसे दशकों से पेंडिंग सुधारों को लागू करने में सरकार के नेशन फर्स्ट अप्रोच की भी तारीफ़ की। डॉक्यूमेंट में नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया, जिसका सबूत आतंकवाद के खिलाफ़ सर्जिकल और क्रॉस-बॉर्डर एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई और गलत सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना है। बयान में कहा गया, नक्सलवाद के खात्मे, नॉर्थ-ईस्ट में परमानेंट शांति समझौतों पर साइन करने और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद के समाधान में भी तारीफ़ के काबिल तरक्की देखी गई है। प्रस्ताव में डिफेंस से लेकर एआई तक के सेक्टर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में तरक्की का क्रेडिट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन से मिली रफ़्तार को दिया गया। साथ ही, इसने G-20 की सफल प्रेसीडेंसी, इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन LiFE जैसी पहलों के ज़रिए भारत की मज़बूत ग्लोबल भूमिका पर ज़ोर दिया। डेवलपमेंट और हेरिटेज (विकास और विरासत) को एक साथ लेकर, टेक्स्ट में एक कल्चरल रेनेसां का ज़िक्र किया गया, जिसका सिंबल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और कर्तव्य पथ है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की भावना से प्रेरित है, जिसने कोविड महामारी जैसे ग्लोबल संकटों को सफलतापूर्वक पार किया। अपनाया गया प्रस्ताव प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की शुभकामनाओं के साथ

गैंगस्टर काला जठेड़ी के नाम पर मांगी तीन करोड़ की रंगदारी, दिल्ली के कारोबारी को अमेरिका से कराया कॉल

नई दिल्ली । उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने एक कारोबारी से गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के बदमाश बनकर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में दो व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी साहिल गर्ग और राजन कालरा के रूप में हुई है। मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाले आरोपी साहिल ने पैसों के लेन-देन के विवाद में दोस्त राजन कालरा और अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले उसके भाई की मदद से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने अमेरिका से काला जठेड़ी के नाम से धमकी भरे कॉल करवाए और वॉयस मैसेज भिजवाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि राणा प्रताप रोड इलाके में रहने वाले रोहित जैन ने आदर्श नगर थाने में अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबरों से रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले ने खुद को हरियाणा के काला जठेड़ी गैंग का बदमाश बताया और व्यवसायी साहिल गर्ग का कथित बकाया पैसा वसूलने की बात कही। धमकी देने वाले ने यह भी दावा किया कि रकम की वसूली के लिए उसने साहिल गर्ग से 50 लाख की टोकन राशि ले रखी है। उसने चेतावनी दी कि रुपये का भुगतान नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहित की बवाना के सेक्टर-5 में प्लास्टिक ग्लू टेप बनाने की फैक्टरी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनका हरियाणा के यमुनानगर निवासी साहिल गर्ग के साथ व्यावसायिक विवाद चल रहा था। पूर्व में साहिल गर्ग ने उसके खिलाफ आदर्श नगर में कथित धोखाधड़ी और 2.95 करोड़ का भुगतान न करने संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी। अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग - पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता को धमकाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तथा एक भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने नामजद आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि आरोपी हरियाणा के करनाल, जगाधरी, यमुनानगर एवं चंडीगढ़ में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस नेआरोपी राजन कालरा को गिरफ्तार कर लिया।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साहिल गर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि राजन कालरा का भाई अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। आरोपी साहिल और राजन ने कारोबारी से पैसे निकालने के लिए साजिश रची। उसके बाद उन लोगों ने खुद को काला जठेड़ी गैंग का बदमाश बनकर वॉयस मैसेज तैयार किया। फिर इन लोगों ने वॉयस मैसेज को राजन के भाई को भेजा। फिर उसके नंबर के जरिये उस मैसेज को कारोबारी को भेजा। विदेश में बैठा गैंगस्टर उसे धमकी दे रहा है।

रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर नई लिफ्ट लगेगी

नई दिल्ली। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने आम जनता की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी है। पहले फैसले के तहत रोहिणी पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर नई लिफ्ट लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को सौंप दी गई है। इस कदम से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही पास के बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों की राह भी आसान हो जाएगी। इससे पूर्व दिल्ली सरकार के भूमि और भवन विभाग ने कुछ नीतिगत वजहों से इस प्रस्ताव को रोक दिया था, लेकिन अब एलजी की मंजूरी के बाद इस पर काम आगे बढ़ेगा। दूसरे बड़े फैसले में दिल्ली में पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के इस्सापुर गांव में एक नया सौर ऊर्जा पूलिंग सब स्टेशन बनाने के लिए ग्राम सभा की नौ बीघा जमीन को बिजली विभाग के लिए मंजूर किया गया है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोलीं-पीएम मोदी ने बिना छुट्टी लिए देश की सेवा की, बनाया नया रिकॉर्ड

नेशनल डेस्क ।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली की किशनगंज गौशाला का दौरा किया और एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि आज वह (मोदी) सबसे लंबे समय तक पद रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और वह बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, देश की सेवा कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई देश का सम्मान बढ़ाने और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, जिसके लिए वह निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं, चाहे वह देशभर में शौचालयों को बढ़ावा देकर उन्हें सम्मान देना हो या उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराकर उनके जीवन को आसान बनाना हो। गुप्ता ने कहा, ÷इस अवसर पर मैं देश की महिलाओं की ओर से भी उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।÷ मोदी ने 10 जून को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

सम्पादकीय...

बगावत कथा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी अत्यंत मुश्किलों का सामना कर रही हैं। पार्टी के 80 में से 58 विधायक पहले ही बगावत कर अपना अलग गुट बना चुके हैं। इस अलग गुट ने ऋत्ब्रत बनर्जी को इस गुट का नेता बनाया है और पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता भी दे दी है। सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी भाग ले रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी के 20 सांसद लोकसभा अध्यक्ष को अपनी निष्ठा बदलने का पत्र दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आज के दौर में सिद्धांत और विचारधारा की कोई कीमत नहीं है। आज के दौर में सुविधा की राजनीति जनादेश से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। पार्टी भी वही है लेकिन वफादारी बदल गई है। पार्टी से अलग होने की घोषणा करने वाले विधायकों और सांसदों की संख्या दो-तिहाई से ज्यादा है इसलिए दलबदल कानून के प्रावधानों का कोई असर उन पर नहीं पड़ेगा। तृणमूल के झंडे और उसकी विचारधारा के नीचे जनता के वोट हासिल कर जीतने वाले जनप्रतिनिधि पार्टी तोड़कर या दलबदल कर लोकतंत्र को कितना मजबूत कर पाएंगे, यह सवाल भी अब पुराना हो चुका है। क्योंकि देश में आया राम-गया राम की संस्कृति कोई नई नहीं है। थोक में दलबदल पहले भी होते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नियति भी महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी जैसी हो चुकी है। आज कानून की नजर में (असली शिवसेना) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है जबकि मराठा क्षत्रप शरद पवार की एनसीपी उन्हीं की परिवार की बहू स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के कब्जे में है। अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद उनके गुट ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री बन गईं। इतिहास को देखा जाए तो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से विद्रोह कर अपनी पार्टी का गठन किया था। ममता बनर्जी ने पहले भाजपा की मदद लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कमजोर किया था, फिर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। 1997 में ममता बनर्जी कांग्रेस में पूरी तरह से अलग-थलग पड़ चुकी थीं और वह अपने बागी तेवर दिखाने लगी थीं। मतभेद इतने बढ़ गए कि ममता बनर्जी ने अपनी राह अलग कर ली। ममता बनर्जी ने जनवरी 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। फरवरी में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए। यह चुनाव उन्होंने भाजपा से समझौता करके लड़ा था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तब कांग्रेस का केवल एक सांसद जीता था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में ममता ने वामपंथियों को साफ किया और कांग्रेस को दूसरे नम्बर पर पछाड़ दिया। कभी ममता ने कांग्रेस की तुलना तरबूज से करते हुए कहा था कि वह ऊपर से हरा लेकिन अन्दर से लाल है। उन्होंने कांग्रेस पर वामपंथियों से सांठगांठ का आरोप लगाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को लेकर कई गलतियां कीं। लगातार तीन कार्यकाल सत्ता में रहने के बाद भ्रष्टाचार, निरंकुश शासन, असहमति का दमन और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारण टीएमसी का पतन लंबे समय से तय था। इन सब ने प्रशासन और पार्टी दोनों में जनता के विश्वास को लगातार कमजोर किया, वहीं अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका ने वरिष्ठ नेताओं की उस पीढ़ी को पार्टी से दूर कर दिया, जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर से खड़ा किया था। मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से थे। वे भतीजे के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे और उन पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी था जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों की जांच कर रही थीं। टीएमसी को सत्ता के लिए राज्य संसाधनों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं था, लेकिन वह भाजपा का सामना नहीं कर सकी, जो खेल के नियमों को और भी आगे बढ़ाने को तैयार है। टीएमसी बनाम टीएमसी की इस लड़ाई में वैध टीएमसी होने का दावा करने वाले दोनों गुटों की स्थिति को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी। यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल की दशकों पुरानी जहरीली राजनीतिक संस्कृति को भी उजागर करता है, जो हिंसा और अवसरवादिता से ग्रस्त है। टूट-फूट के बीच केन्द्र सरकार भी अपना समीकरण बनाने में जुटी हुई है। एनडीए सरकार को हाल ही में तब झटका लगा जब संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, या डिलिमिटेशन बिल, जो चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने और लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने की कोशिश करता है, वह अप्रैल में लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से कम रहने पर गिर गया। सरकार इस कानून को फिर से लाने और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले वन नेशन-वन इलेक्शन बिल लाने पर भी विचार कर रही है। हाल के विधानसभा चुनावों में टीएमसी और डीएमके को लगी झटकों के साथ बीजेपी लीडरशिप ने भी डीएमके से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिसने सूत्रों के मुताबिक केंद्र को मुद्दों पर आधारित समर्थन पर विचार करने की इच्छा दिखाई है। केन्द्र सरकार परिसीमन बिल पर एक संशोधित प्रारूप तैयार कर रही है, जिसमें बीएनके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की उठाई गई खास चिंताओं को दूर किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में टीएमसी का बागी गुट और डीएमके परिसीमन बिल पर सरकार को समर्थन देता है तो भाजपा बिल पास कराने में मुश्किल नहीं आएगी। आज की राजनीति में सत्ता का सिर थामने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। सिद्धांतों, राजनीतिक मर्यादाओं और लोकलज्जा की परवाह किसी को भी नहीं है।

गोरखपुर का चिलुआताल ईको-टूरिज्म और नौकाविहार का बना नया केन्द्र

जनपद गोरखपुर अपने समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा तथा गौरवशाली इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का गोरखनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, गीता प्रेस तथा शहीद स्मारक आगन्तुकों एवं पर्यटकों को आकर्षित करते है। अन्य स्थानों में यहाँ का रामगढ़ताल, पुरातात्विक बौद्ध संग्रहालय तथा नक्षत्रशाला आदि पर्यटकों को आकर्षित करते है। इसी कड़ी में चिलुआताल को ईको-टूरिज्म तथा वाटर स्पोर्ट्स के नए केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी हाल में ही प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 20.39 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण किया। गोरखपुर के उत्तरी छोर पर चिलुआताल एक प्राकृतिक झील है। जिसे ईको-टूरिज्म और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चिलुआताल के सौन्दर्यीकरण से न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से आये पर्यटकों को एक सुन्दर पिकनिक स्पॉट तथा प्राकृतिक स्थल पर घूमने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्राकृतिक झील के विकास से आस-पास के स्थलों की व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, साथ ही लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा रोजगार प्राप्त होगा। डबल इंजन की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है, इस सेक्टर में निवेश एवं रोजगार की अपार सम्भावनाएं है। 20.39 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित परियोजना को जनता को समर्पित करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पिछली सरकारों के दौर में ताल-पोखरों पर अवैध कब्जे होते थे और गन्दगी व अपराध के केन्द्र बन जाते थे। वर्तमान सरकार ऐसे जलाशयों को संरक्षित कर उन्हें जनउपयोगी और पर्यटन विकास से जोड़ रही है। चिलुआताल का प्राकृतिक स्वरूप इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसका पानी पूरी तरह से प्राकृतिक स्रोतों से आता है। इसके अलावा चिलुआताल का शांत और स्वच्छ वातावरण पर्यटन के लिए बेहद अनुकूल बनाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से चिलुआताल में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 20 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण में मदद भी करेगी। पूर्व में चिलुआताल भी रामगढ़ताल की तरह दशकों से उपेक्षित रहा है। वर्तमान सरकार ने पहले रामगढ़ताल का कायाकल्प करके उसे वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। अब चिलुआताल को भी सँवारा जा रहा है। यूपी प्रोजेक्टस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर कराये गये कार्यों में 570 मी0 पाथवे का निर्माण घाट की सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, बेन्च 400 मी0 एप्रोच रोड तथा 500 मी0 सड़ड वाल का निर्माण आदि शामिल है। रामगढ़ताल के नौकाविहार की तरह विकसित होने से चिलुआताल की आभा निखर कर सामने आ रही है। स्थानीय लोग सुबह-शाम टहलने के लिए आना शुरू कर दिये है। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन से विकसित चिलुआताल टूरिस्ट स्पॉट मनोरंजन के साथ-साथ रोजगार का केन्द्र भी बनेगा। यहाँ पर कई दुकानें बन कर तैयार है, घाट पर एक तरफ लोग सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मनोरंजन का लाभ प्राप्त करेंगे, वहीं स्थानीय व्यन्जन का लाभ भी उठा सकेंगे। चिलुआताल में भी रामगढ़ताल की तरह लोगों को बोटिंग करने तथा वाटर स्पोर्ट्स का आनन्द प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में पर्यटन अवसरों के सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। धार्मिक स्थलों से लेकर ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों को सहेज कर नई पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा रहा है। यह सभी स्थल हमारी सांस्कृतिक चेतना के केन्द्र है। प्रदेश के विकसित यह स्थल प्रदर्शित करते है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक सम्पदा कितनी समृद्धशाली है। इन स्थलों तक पहुँचने के लिए पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। पर्यटक/श्रद्धालु कम समय में पसंदीदा स्थल तक पहुँच सकते है। इसके लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने के कारण प्रदेश में पर्यटकों के आगमन में कई गुना वृद्धि हुई है। धार्मिक स्थलों में काशी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, कुशीनगर में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

इसके साथ ही इस सेक्टर में निवेश भी बढ़ रहा है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल रही है। इसके अलावा ईको-टूरिज्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। महेसरा ताल (चिलुआताल) में फ्लोटिंग सोलर परियोजना से बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की हरित ऊर्जा शक्ति उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से उभरते औद्योगिक और निवेश केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य न केवल उद्योग, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में गोरखपुर की कंपनी नॉर्दर्नएक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा.लि. द्वारा महेसरा ताल (चिलुआताल) में 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित कराना उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परियोजना केवल एक व्यावसायिक सफलता नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक क्षमता, स्थानीय उद्यमों की दक्षता तथा हरित ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। गोरखपुर स्थित महेसरा ताल, जिसे चिलुआताल के नाम से भी जाना जाता है, अब देश के महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में अपनी पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह प्रतिष्ठित फ्लोटिंग सोलर परियोजना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी। परियोजना के लिए देशभर की 25 प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। कठोर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 17 कंपनियों को योग्य घोषित किया गया। 25 मई 2026 को सफल वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत लगभग 115 करोड़ रुपये मूल्य की यह परियोजना गोरखपुर की कंपनी नॉर्दर्न एक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा.लि. को प्रदान की गई।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की स्थानीय कंपनियां अब देश की बड़ी और जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने की क्षमता रखती है। यह उपलब्धि प्रदेश के उद्यमशील वातावरण और निवेश-अनुकूल नीतियों का भी परिणाम है। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं जलाशयों, झीलों और तालाबों की सतह पर स्थापित की जाती है। इन परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही जल की सतह पर लगे सोलर पैनल अपेक्षाकृत कम तापमान पर कार्य करते है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। चिलुआताल में स्थापित होने वाली यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ जल संरक्षण में भी सहायक होगी। इससे जल वाष्पीकरण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में जब देश ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब इस प्रकार की परियोजनाएं सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

यह पीएम नरेन्द्र मोदी का युग है

नरेन्द्र मोदी अनजाने में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस कथन पर भरोसा करते नजर आते है कि उन्होंने कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता चुना और शायद इसी से सारा फर्क पड़ा। जवाहरलाल नेहरू और नरेन्द्र मोदी के रूप में भारत के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व के दो अलग-अलग युगों का प्रतिनिधित्व होता है। इनमें से प्रत्येक युग को उनकी सीमाओं, पसंदगियों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। नेहरू ने जहां एक नाजुक एवं नवगठित संप्रभु राष्ट्र की अगुवाई की, वहीं मोदी ने वैश्विक झटकों से जूझते हुए एक विशाल, डिजिटल रूप से जुड़े एवं अति-प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र के शासन को संभाला है। नेहरू का शासन संबंधी दर्शन ऊपर से नीचे की ओर संस्थाओं के निर्माण और राज्य-निर्देशित अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित था। मोदी का दृष्टिकोण उस तरीके को उलट देता है और शासन को गरिमा एवं कार्यान्वयन द्वारा संचालित एक जन आंदोलन --सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास-- के रूप में स्थापित करता है। बैंक खातों, डीबीटी, किफायती गैस कनेक्शन, आवास, शौचालय, तेज गति से सड़क निर्माण और डिजिटल कल्याणकारी योजनाओं जैसी नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली यह लामबंदी राज्य से मिलने वाले फायदों को परिवार के स्तर पर दृश्यमान बनाती है जिससे परिणामों के साथ-साथ भरोसा भी बढ़ता है। आकार ही दोनों नेताओं के कार्यकालों के बीच का मुख्य अंतर है। नेहरू ने जिस समय पदभार संभाला तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ और दलीय प्रतिस्पर्धा नगण्य थी। मोदी के सत्ता संभालने के वक्त देश की आबादी 131 करोड़ से अधिक और एक ऐसी दलीय प्रणाली सामने थी जिसमें हजारों पंजीकृत संस्थाओं का अस्तित्व था और आम चुनाव के मतपत्रों में सैकड़ों संस्थाओं की मौजूदगी थी। भारत के पहले आम चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था। जबकि, 2014 में मतदाताओं की तादाद 83 करोड़ से अधिक हो गई थी तथा 2024 तक इसमें और भी बढ़ोतरी हुई। मोदी को बार-बार राष्ट्रीय जनादेश इस तीखे विखराव और चौबीसों घंटे सातों दिन डिजिटल निगरानी के बावजूद हासिल हुए है। पल-पल की डिजिटल निगरानी वाला मीडिया का यह माहौल नेहरू काल की संस्था-आधारित व प्रिंट-युग की राजनीति से बिल्कुल ही अलग है। निरंतर ऑनलाइन आलोचनाओं के बीच शासन चलाने से जवाबदेही और कथनात्मक प्रतिस्पर्धा की गति तेज हो जाती है। तीन लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी का चुनावी रूप से केन्द्र में बने रहना और कई परिवारों के तीन पीढ़ियों के जेहन में प्रासंगिक बने रहना। नेटवर्क के इस युग में उनकी असाधारण राजनीतिक स्थिरता को दर्शाता है। आर्थिक दृष्टि से, नेहरू के मॉडल ने आधारभूत उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थानों को तराशा, लेकिन आखिरकार वह 3-4 प्रतिशत के आसपास की --हिंदू विकास दर-- के रूप में जानी जाने वाली दर पर स्थिर हो गया। मोदी की अगुवाई वाला भारत वैश्विक विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है और कोविड-19, मुद्रास्फीति में उछाल, आपूर्ति शृंखला में झटके तथा भू-राजनीतिक संघर्षों से ग्रस्त एक दशक के दौरान इसकी औसत वृद्धि दर लगभग 6.5-7 प्रतिशत की रही है। सामाजिक स्तर पर, मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की संरचना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के प्रतिनिधित्व को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है

और महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1950 के दशक में निम्न इकाई अंकों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए बढ़कर एक तिहाई आरक्षण के रिश्तायी मार्ग तक पहुंच गया है। यह सांकेतिक समावेशन से आगे बढ़कर संरचनात्मक भागीदारी की दिशा में होने वाले बदलाव को इंगित करता है। विदेश नीति में शैलीगत और रणनीतिक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता सैद्धांतिक थी, लेकिन वह द्विध्रुवीय विश्व में अक्सर अलग-थलग पड़ने का कारण बनी और भौतिक शक्ति की तुलना में नैतिक नेतृत्व पर अधिक आधारित थी। मोदी की विभिन्न शक्तियों के साथ जुड़ाव की नीति लेन-देन पर आधारित, बहु आयामी और स्पष्ट रूप से हितों पर केन्द्रित है। एक ही साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और ग्लोबल साउथ के साथ संबंध स्थापित करना और भारत के बाजार, प्रौद्योगिकी की मांग और प्रवासी भारतीयों के प्रभाव को सौदेबाजी की शक्ति में बदलना इसका बेहतरीन उदाहरण है। विदेशों में संसदीय संबोधनों की आवृत्ति और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों का अंबार एक गहरी हकीकत के लक्षण है = भारत आज आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन से लेकर डिजिटल लोक कल्याण तक के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें आकार दे रहा है। सुरक्षा और शासन कला में भी बदलाव आया है। नेहरू के शासनकाल को अक्सर -क्षतिपूर्ण- काल के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उस दौरान भी कई संघर्ष हुए प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध से लेकर 1962 में चीन के साथ हुए संघर्ष तक। मोदी की नीति में प्रतिरोध, सुनियोजित प्रतिक्रिया और सक्रिय सीमा प्रबंधन का समावेश किया गया है ताकि अस्थिर पड़ोस में बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध से बचा जा सके। भारत फिर भी एक प्रमुख कृषि उत्पादक एवं निर्यातक देश बना हुआ है। यह सिर्फ कल्याणकारी होने भर का मामला नहीं है। बल्कि यह एक ऐसी व्यापक स्थिरता है जो परिवारों को सहारा देती है ताकि वे शिक्षा, गतिशीलता और रोजगार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। पर्यावरण और सभ्यतागत संरक्षण के संदर्भ में नेहरू का काल आधुनिक संरक्षण व्यवस्थाओं से पहले का चरण था। मोदी के युग में संरक्षित क्षेत्रों, बाघ अभयारण्यों, रामसर स्थलों का विस्तार हुआ है और चीतों का ऐतिहासिक पुनर्प्रवेश हुआ है। इकोलॉजी के विस्तार के समानांतर, सभ्यता का सुनियोजित पुनर्केंद्रीकरण भी किया गया है। ये जनसांख्यिकीय बदलाव एक ऐसे राज्य की मांग करते हैं जो सेवाओं का तेजी से विस्तार करने के साथ-साथ गुणवत्ता को भी बढ़ाए। यही वो दोहरी चुनौती है जिससे मोदी का शासन मॉडल डिजिटल सुविधाओं और संस्थागत प्रसार के जरिए निपटना चाहता है।

पीएम मोदी का कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है तथा उन्होंने इंदिरा गांधी के सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। वे नेहरू के निरंतर सेवा के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदों पर निर्वाचित प्रमुख के रूप में देश में कुल मिलाकर सबसे लंबा कार्यकाल हासिल कर लिया है। एक ऐसा भारत जो पहले से कहीं बड़ा, अधिक गतिशील, अधिक जुड़ा हुआ, अधिक प्रतिस्पर्धी है -- और फिर भी कई लोगों की सोच से कहीं अधिक शासन योग्य है। संप्रभुता, संसदीय संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और संस्थागत आधार। मोदी की खासियत इसके व्यापक कार्यान्वयन में है।

प्रजनन दर में गिरावट का एक नया गुनहगार - स्मार्टफोन!

विशेषज्ञ लंबे समय से यह सोच रहे थे कि क्या फोन ने जन्म दर में गिरावट में कोई भूमिका निभाई है, जो 2007 में शुरू हुई थी, उसी वर्ष, जब एप्पल ने आईफोन पेश किया था लेकिन अब तक इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। दो नए शोध पत्र, जिनमें से एक गत सोमवार को और दूसरा मई में प्रकाशित हुआ, पहले ऐसे शैक्षणिक प्रयास है, जो यह जांचते है कि क्या स्मार्टफोन इसका एक कारण था? ये पिछले 20 वर्षों में अमेरिका और अन्य देशों में प्रजनन दर में आई व्यापक गिरावट को समझाने के सबसे हालिया प्रयास है। शोधकर्ता पहले ही गर्भनिरोधक के उपयोग, गर्भपात की दरों, महिलाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि और यहां तक कि लोकप्रिय टैलीविजन शो '16 एंड प्रैग्नेंट' पर भी गौर कर चुके है। यह साबित करना कि फोन के कारण यह गिरावट आई है, एक जटिल काम है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए सबसे बेहतरीन पैमाना 'रैंडम असाइनमेंट' के रूप में जाना जाता है। यह उन लोगों के परिणामों की तुलना करता है जिन्हें बेतरतीब ढंग से कोई ट्रीटमेंट (जैसे स्मार्टफोन मिलना) देने के लिए चुना जाता है, उन लोगों से जिन्हें वह नहीं मिलता। लेकिन घटती प्रजनन दर के कारणों का पता लगाने के मामले में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन के बारे में ऐसा डेटा तलाशा, जो इसमें रैंडमनेस लाता हो। मिडिलबरी कॉलेज की अर्थशास्त्री कैटिलिन मायर्स और उनके छात्र एजेकिएल ह्यूर ने प्रजनन क्षमता पर फोन के प्रभावों को अलग करने के लिए आईफोन के शुरुआती दौर के असमान और बिखरे हुए रोलआउट (शुरुआत) का उपयोग किया। उन्होंने लिखा कि पहला आईफोन जून, 2007 में जारी किया गया था और यह फरवरी 2011 तक केवल 'AT&T' नेटवर्क पर ही उपलब्ध था। इस अध्ययन ने उन अमेरिकी काउंटियों में प्रजनन दरों की तुलना की, जहां लगभग हर जगह AT&T का कवरेज था, उन काउंटियों से जहां यह कवरेज बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में प्रकाशित उनके पेपर में पाया गया कि आईफोन 2007 और 2011 के बीच फर्टिलिटी में आई गिरावट के आधे हिस्से तक की वजह बना। सबसे स्पष्ट प्रभाव 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में देखे गए। आईफोन वाली काउंटियों में क्या हुआ? प्रोफेसर मायर्स ने कहा कि एक सिद्धांत यह है कि युवाओं ने अपने फोन पर अधिक और व्यक्तिगत रूप से कम मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया तथा इसके परिणामस्वरूप उनके संबंध बनाने और गर्भवती होने की संभावना कम हो गई। प्रोफेसर मायर्स ने कहा कि आईफोन ने पोर्नोग्राफी को भी अधिक सुलभ बना दिया होगा, जिससे युवाओं ने इसे यौन संबंध के विकल्प के रूप में अपना लिया, या युवाओं ने गर्भधारण से बचने के लिए बेहतर जानकारी प्राप्त करने हेतु इसका उपयोग किया हो सकता है, जिसमें गर्भनिरोधक और गर्भपात शामिल है। इस अध्ययन में शामिल नहीं रहे शोधकर्ताओं ने कहा कि ये परिणाम ठोस और आश्वस्त करने वाले थे। घटती जन्म दर, जो कभी अमीर समाजों की विशेषता हुआ करती थी, अब एक लगभग वैश्विक घटना है। इस गिरावट के व्यापक प्रसार ने शोधकर्ताओं को इसके सामान्य चालकों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरे अध्ययन के लेखकों ने भी स्मार्टफोन पर गौर करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हरनान मोस्कोसो बोएदो और पीएच.डी. छात्र नाथन हड्सन ने 128 देशों में स्मार्टफोन की पहुंच और किशोर प्रजनन दरों को मापने वाले विश्व बैंक के आंकड़ों का विश्लेषण किया।

मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही कांग्रेस का घमंड भी चकनाचूर कर दिया है

नीरज कुमार दुबे

मोदी है तो मुमकिन है, यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि पिछले बारह वर्षों में भारत की बदलती राजनीतिक और प्रशासनिक तस्वीर का सबसे सशक्त प्रतीक बन चुका है। जिस उपलब्धि को दशकों तक असंभव माना जाता रहा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभव कर दिखाया है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। लगातार 4399 दिनों तक देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के 4398 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। देखा जाये तो यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड टूटने भर की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में आए एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है बल्कि उस राजनीतिक सोच को भी चुनौती दी है जिसमें लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सत्ता पर केवल एक ही परिवार या एक ही दल का स्वाभाविक अधिकार है। दशकों तक देश की राजनीति गांधी परिवार और कांग्रेस पर केंद्रित रही, लेकिन एक गरीब परिवार से निकले, संघर्षों के बीच पले-बढ़े और कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचकर भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मोदी का यह सफर करोड़ों सामान्य भारतीयों के लिए प्रेरणा का विषय है। यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, और जनता जब ठान ले तो वह किसी भी स्थापित राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाकर नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विजन और जनता के भरोसे के दम पर भारतीय राजनीति में असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते है। देखा जाये तो मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस जनविश्वास की कहानी है जिसने नरेंद्र मोदी को लगातार तीन बार देश की सत्ता सौंपी। आजादी के बाद केवल जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी ने भी वही करिश्मा दोहराया, लेकिन उससे आगे जाकर लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक नेता बनकर उभरेंगे। 2019 में उन्होंने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश हासिल किया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से नीचे रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चमक और प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सत्ता संभाली और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दरअसल नरेंद्र मोदी का यह सफर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशासन संभालते हुए सुशासन का एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 4610 दिनों तक राज्य की कमान संभाली। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मिलाकर मोदी अब नौ हजार दिनों से अधिक समय तक किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख रह चुके है। मार्च 2026 में उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले निर्वाचित प्रमुख बन गए थे। उधर, मोदी के इस ऐतिहासिक मुकाम पर केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयों का सिलसिला मिला। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों का उल्लेख किया। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने इसे दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का प्रमाण बताया। अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्निन ने मोदी के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों के विश्वास ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी मोदी की उपलब्धि को भारत की समृद्धि, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा से जोड़ा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को समर्पण, संघर्ष और जनसेवा का प्रतीक बताया। यह साफ संकेत है कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के नेता नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके है। उधर, देश के भीतर भी मोदी की इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। भाजपा नेताओं ने आज देशभर के विभिन्न धर्म स्थलों में प्रार्थना कर भारत की खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने की कामना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की। इसके अलावा, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की गयी और एक अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनन्दन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। बहरहाल, नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उन्होंने खुद को केवल एक नेता नहीं, बल्कि बदलाव के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला यह सफर आज करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन चुका है। यही कारण है कि जब देश की राजनीति में असंभव को संभव करने की बात होती है, तब एक ही आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है- मोदी है तो मुमकिन है।

यह साफ संकेत है कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के नेता नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। उधर, देश के भीतर भी मोदी की इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। भाजपा नेताओं ने आज देशभर के विभिन्न धर्म स्थलों में प्रार्थना कर भारत की खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने की कामना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंटालेना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ खोला मोर्चा

नेबुआ नौरंगिया/कुशीनगर। पडरौना तहसील क्षेत्र के सरंगटिया उर्फ रामनगर गांव में सरकारी भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने गांव के पूर्व प्रधान पर सरकारी पट्टा दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करने तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की लगभग 18 एकड़ सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है। इस संबंध में कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते भूमिहीन एवं पात्र परिवार सरकारी भूमि के लाभ से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान ने कई लोगों को सरकारी भूमि का पट्टा दिलाने का आश्वासन देकर उनसे 20 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की रकम वसूली। ग्रामीणों के अनुसार इस प्रक्रिया में करीब 10 लाख रुपये की वसूली की गई, लेकिन न तो किसी को पट्टा मिला और न ही भूमि का आवंटन किया गया। आरोपों से नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व प्रधान सहित कथित कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई।

जून भर बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

पडरौना, कुशीनगर। राजकीय महिला चिकित्सालय पडरौना के पीपी यूनिट मॉडल टीकाकरण केंद्र पर मंगलवार को विटामिन ए सम्पूर्ण अभियान÷ का शुभारंभ किया गया। महिला चिकित्सालय की चिकित्साधिकारी डॉ. ज्योति सिंह ने फीता काटकर अभियान का उद्घाटन किया तथा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉ. ज्योति सिंह ने बताया कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक है। इसकी नियमित खुराक बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही कुपोषण और विभिन्न

बीमारियों से बचाव में सहायक होती है। उन्होंने अभिभावकों से अभियान का लाभ उठाने और निर्धारित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की। कार्यक्रम में एएनएम पूजा यादव, काउंसलर आशा गुप्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्त्रियां, सीडीपीओ श्रीमती मुनमुन देवी, डब्ल्यूएचओ के एसआरटीएल डॉ. गुलाम अहमद, बीएचडब्ल्यू सुमित श्रीवास्तव, बीएचडब्ल्यू प्रमोद कुमार, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम) तथा ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम) सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान रेडियो प्रज्ञा के तेज नारायण श्रीवास्तव, आरजे अमन, आरजे सोनिया तथा अन्य सहयोगियों ने भी सहभागिता की। अधिकारियों ने बताया कि विटामिन ए सम्पूर्ण अभियान पूरे जून माह तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।

पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा- तीन दिनों में 30,963 अभ्यर्थी अनुपस्थित

गोरखपुर।

जनपद में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच सकुशल संपन्न हो गई। 8 जून से 10 जून तक तीन दिनों में कुल 6 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में जहां प्रशासन ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए, वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। आंकड़ों के अनुसार, तीन दिनों में कुल 1,16,784 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 30,963 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहले दो दिनों में ही 20,921 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, जबकि तीसरे और अंतिम दिन भी 10,042 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। तीसरे दिन की बात करें तो प्रथम पाली में 19,464 में से 14,411 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5,053 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 19,464 में से 14,477 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 4,989 अभ्यर्थी

अनुपस्थित रहे। इस तरह अंतिम दिन कुल 10,042 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। इससे पहले पहले दिन 10,691 और दूसरे दिन 10,230 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। लगातार तीन दिनों तक बड़ी संख्या में अनुपस्थिति ने प्रशासन का ध्यान जरूर खींचा है, हालांकि परीक्षा की व्यवस्था और संचालन पूरी तरह व्यवस्थित रहा। जनपद में इस परीक्षा के लिए कुल 44 केंद्र बनाए गए थे, जहां प्रत्येक पाली में 19,464 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, वहीं यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू रहा। परीक्षा के दौरान डीआईजी एस. चन्नप्पा, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार और एसपी सिटी निमिष पाटिल सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का

आखिरी दिन भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, कुल 6 पालियों में 1,16,784 को देना था एग्जाम

सख्त सुरक्षा, पारदर्शी व्यवस्था के बीच गोरखपुर में सकुशल संपन्न हुई परीक्षा

जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कड़ाई के साथ संपन्न कराया गया। तीनों दिनों में परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। कुल मिलाकर, गोरखपुर में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रशासनिक सतर्कता और सुदृढ़ व्यवस्था का उदाहरण बनकर सामने आया, जिससे अभ्यर्थियों और आम जनता के बीच व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

कुशीनगर।

कसया तहसील सभागार में बुधवार को ÷सरकार आपके द्वार÷ विशेष जनसंपर्क एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक पी.एन. पाठक के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आमजन तक सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है।

कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं का गोदभराई संस्कार एवं बच्चों का अन्नप्राशन समारोह संपन्न कराया गया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें पोषण संबंधी आवश्यक परामर्श दिए गए। शिविर में टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया गया। उपस्थित लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया गया। विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा विदेश नीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी संतराज सिंह बघेल ने की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अद्या पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल, फाजिलनगर अध्यक्ष सुनीता शाही, राकेश जायसवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रतिभा सम्मान समारोह में के.के. पब्लिक एकेडमी के छात्रों ने बढ़ाया मान

भटनी देवरिया।

नगर पालिका परिषद देवरिया के सभागार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में के.के. पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी, भटनी के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा 2026 में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय के कक्षा 12 के छात्र आयुष विश्वकर्मा (93.6फीसदी), अभिनव राय (83फीसदी) एवं नैना मिश्रा (82.6फीसदी) तथा कक्षा 10 की छात्रा पिंकी सिंह (90.4फीसदी), आकांक्षा यादव (89.6फीसदी) एवं छात्र अर्पित प्रजापति (89फीसदी) को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में खुशी का माहौल रहा। यह सम्मान समारोह वर्ष 2026 की यू.पी. बोर्ड,

सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, अलका सिंह, दिलावर सिंह तथा वरिष्ठ शिक्षक एवं पत्रकार मारकंडे मिश्र उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को

***यू.पी. बोर्ड, सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड**
***बोर्ड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को मिला सम्मान**

सम्मानित करते हुए कहा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण, अनुशासन और सतत परिश्रम से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक रहने का संदेश दिया। विद्यालय परिवार ने सम्मानित छात्र-छात्राओं की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अभिभावक, शिक्षक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

डीएम ने किया ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, एनक्यूएएस मानकों के अनुसार तैयारियां तेज करने के आदेश

देवरिया।

ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाने और मातृ-शिशु सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करौदी में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के टीकाकरण सत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की इस बुनियादी विधिक व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सत्र के दौरान जिलाधिकारी ने एएनएम और आशा कार्यकत्रियों से उपलब्ध टीकों, आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का टीकाकरण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार हर हाल में पूरा किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की हिदायत देते हुए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) के सभी कालमों को वास्तविक तथ्यों और सही चिकित्सकीय डेटा के आधार पर भरने पर विशेष बल दिया, ताकि प्रसव पूर्व और बाद की निगरानी पारदर्शी रहे। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र परसिया मिश्र पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) के कड़े मानकों के अनुरूप चल रही प्रशासनिक तैयारियों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र को राष्ट्रीय प्रमाणन दिलाने के लिए तय मानकों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं और चिकित्सकीय सुविधाएं समय से पूरी की जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को और बेहतर एवं उच्च स्तरीय उपचार मिल सके। इस दौरान विभागीय अधिकारी और स्थानीय पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा।

ओम बिरला बोले- कानूनों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन ही सुशासन, जनसेवा के प्रति समर्पण प्रत्येक आईएएस का अनिवार्य गुण

नेशनल डेस्क ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कानूनों और नीतियों को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है। बिरला ने संसद भवन में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपनी सेवा को केवल एक पेशा न मानें, बल्कि संविधान, राष्ट्र और नागरिकों के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि लोक सेवक नागरिकों की आकांक्षाओं को वास्तविक परिणामों में बदलने वाले परिवर्तन के वाहक होते हैं। संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि देश की जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि संसद के साथ जुड़ाव से प्रशिक्षु अधिकारियों को लोकतांत्रिक शासन, विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने अधिकारियों से अपने संसदीय अनुभव का उपयोग लोक प्रशासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बेहतर समझ विकसित करने के लिए करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी प्रक्रिया को समग्र रूप से समझने पर बल देते

हुए कहा कि संसद कानून बनाती है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र उन कानूनों की मंशा को नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसी भी कानून का वास्तविक मूल्य उसके प्रभावी क्रियान्वयन में निहित होता है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को आवाज देते हैं, जबकि प्रशासक नीतियों, योजनाओं और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से उन अपेक्षाओं को धरातल पर उतारते हैं। बिरला ने प्रशिक्षु अधिकारियों को जनता से जुड़े रहने और भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताओं को समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक सफल प्रशासक के लिए कानूनों और नियमों का ज्ञान जितना आवश्यक है, उतनी ही महत्वपूर्ण संवेदनशीलता, सहानुभूति और स्थानीय परिस्थितियों की समझ भी है। स्थानीय भाषाओं में संवाद करने और लोगों की समस्याओं को समझने वाले अधिकारी अधिक प्रभावी ढंग से जनविश्वास अर्जित कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सिविल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान देश की शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना रहा है। उन्होंने ईमानदारी, करुणा, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति समर्पण को प्रत्येक सिविल सेवक के लिए अनिवार्य गुण बताया।

मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा,

लगातार सबसे ज्यादा दिनों से इलेक्टेड पीएम

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बुधवार को एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। वह लगातार 4399 दिनों तक चुने हुए सरकार के मुखिया रहने वाले भारत के पहले नेता बन गए।

इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बैठक के दौरान एक बहुत ही अनौपचारिक और दोस्ताना पल उस समय देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथी नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की

मशहूर झालमुड़ी का आनंद लिया। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को झालमुड़ी परोसी। वहीं, पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से सहयोगियों को झालमुड़ी बांटी। पीएम मोदी ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर भी साझा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नेताओं के साथ झालमुड़ी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल?

भारत मंडपम में हुई इस बैठक में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई राज्यों के उपमुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे।

कैसे बना यह कीर्तिमान?

प्रधानमंत्री मोदी ने चुने हुए सरकार प्रमुख के तौर पर 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

इस तुलना के लिए नेहरू के 1952 के बाद के कार्यकाल को आधार माना गया है, क्योंकि 1947 से 1952 के बीच वे अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 साल से ज्यादा समय तक पद संभाला, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस वजह से पीएम मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए सरकार प्रमुख बन गए हैं।

पीएम मोदी ने नेताओं के साथ खाई झालमुड़ी, भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में दिखा खास पल

ट्रम्प बोले- ईरान ने समझौता नहीं किया, कीमत चुकाएगा

खुद को दबंग समझता था, अब खत्म; ईरान की 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

तेल अवीव । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है। नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वह खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने समझौते पर बातचीत करने में बहुत बड़ा देर कर दी। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ईरान ने बुधवार को बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी रडार ठिकानों पर हमले किए थे। इससे पहले सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। ईरान ने अमेरिकी हेलिकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है।

कोचिंग फायरिंग केस- एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर

नेशनल डेस्क । खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी मामले में खान सर दर्ज केस को रद्द कराने को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट के सामने आया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। आप को बता दें कि खान को बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने आज अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी है। इसके बाद शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने ऊपर दर्ज केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि अब बिहार सरकार को अपना जवाब 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। आप को बता दें कि अदालत ने दूसरे पक्ष जान बिंदु के निदेशक यशराज आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने खान सर की ओर से मामले में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की। सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए मामले की केस डायरी तथा खान सर के आपराधिक इतिहास की मांग पुलिस से की है। खान सर के वकील ने इस बीच अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक दिया, लेकिन उन्हें निर्देश दिए हैं कि वह पुलिस को अनुसंधान में मदद करेंगे और जब भी पुलिस उन्हें तलब करेगी, वह हाजिर होंगे।

पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी, 40 लाख से अधिक नए वोटर बढ़े

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025-26 की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। व्यापक पुनरीक्षण, दावे-आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन प्रक्रिया के बाद जारी सूची में राज्यभर में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 मतदाता दर्ज किए गए हैं। पुनरीक्षण के दौरान 1 करोड़ 81 लाख 96 हजार 367 नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया, जबकि 1 करोड़ 41 लाख 76 हजार 809 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से हटाए गए। इसके परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में शुद्ध रूप से 40 लाख 19 हजार 558 की वृद्धि हुई है। जारी आंकड़ों के अनुसार लखनऊ जिले में अंतिम मतदाता सूची में 10 लाख 85 हजार 180 मतदाता शामिल हैं। वहीं प्रयागराज में 34 लाख 95 हजार 203, गोरखपुर में 29 लाख 63 हजार 142 और वाराणसी में 17 लाख 93 हजार 504 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने वर्तमान प्रधानों को छह माह तक प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। उधर, पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आयोग को जिलावार सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट छह माह के भीतर सरकार को सौंपनी है। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हालांकि कई जिलों में मतदाता सूची ओवरलैप करने में तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मतदाता आसानी से अपना नाम सूची में देख सकें।

राम मंदिर दानपात्र प्रकरण : सच बोलूंगा तो परेशानी में पड़ जाऊंगा- बृजभूषण शरण सिंह

गोंडा ।

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विश्नोहरपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राम मंदिर दानपात्र प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं और यदि वह अभी पूरी सच्चाई बता देंगे तो स्वयं बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहते, लेकिन समय आने पर पूरे मामले का सच सामने रखेंगे। कई दिनों बाद दिल्ली से गोंडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले लंबे समय से वह दिल्ली में महिला पहलवानों से जुड़े विवाद के कारण व्यस्त थे और उसी मामले को संभालने में लगे हुए थे। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि किसी मंत्री के इस्तीफा देने से पेपर लीक की घटनाएं बंद नहीं हो जाएंगी। उनके अनुसार पेपर लीक के पीछे एक संगठित तंत्र काम करता है, जिसमें कई स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों को पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री हर परीक्षा केंद्र या हर विभाग की निगरानी स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना ही समस्या का स्थायी समाधान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे, तब तक भाजपा के सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं होगी।

ममता को सबसे बड़ा झटका- टीएमसी के 19 सांसद बागी गुट में शामिल, लिस्ट में यूसुफ पठान-शत्रुघन सिन्हा का भी नाम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी अब एक बड़े सियासी विस्फोट में बदल चुकी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक, टीएमसी अभी सीधे दो हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ी है। दूसरी ओर बंगाल की सियासत और राजनीतिक गलियारों में उठापटक और तेज तब हो गई, जब ये दावा किया जाने लगा कि इन बागी सांसदों में ममता बनर्जी की करीबी सियाली घोष के साथ आसानसोल से सांसद शत्रुघन सिन्हा और बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से बागी सांसदों की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें राय के अलग-अलग हिस्सों से चुनकर आए ये सांसद कथित तौर पर शामिल हो चुके हैं। इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर जारी बगावत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। जादवपुर से सांसद सायोनी घोष और कोलकाता दक्षिण की सांसद माला राय के भी विद्रोही खेमे में शामिल होने की संभावना ने तृणमूल सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले अलग गुट को समर्थन देने की सहमति जताई है।

मीनाक्षी नटराजन मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी, 4 घंटे बाद भी फैसला नहीं, कांग्रेस का धरना जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला अब राजनीतिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए लगातार विरोध दर्ज करा रही है, जबकि पार्टी की नजर अब निर्वाचन आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।बुधवार को कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के फैसले को चुनौती दी। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। आयोग के समक्ष कांग्रेस ने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस आधार पर खारिज किया गया, उसका चुनावी कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला लंबित नहीं था, जिसकी जानकारी शपथ पत्र में देना अनिवार्य हो। उनके अनुसार हैदराबाद की अदालत से केवल एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें आगे सुनवाई शुरू करने को लेकर जवाब मांगा गया था। इसे लंबित आपराधिक प्रकरण मानना कानून की गलत व्याख्या है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को दो घंटे के भीतर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। हालांकि चार घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आयोग की ओर से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। इधर राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पार्टी कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय का मुख्य द्वार बंद मिलने पर उन्होंने कार्यालय के बाहर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाला बताया है। गौरतलब है कि मंगलवार को चुनाव अधिकारियों ने शपथ पत्र में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। भाजपा का आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद की अदालत में लंबित एक मामले की जानकारी हलफनामे में छिपाई। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए लोकतंत्र की हत्या और राज्यसभा सीट की चोरी करार दे रही है। अब पूरे मामले में सभी की निगाहें निर्वाचन आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यह निर्णय न केवल मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का भविष्य तय करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक दिशा भी प्रभावित कर सकता है।

अब 3 महीने में निपटाने होंगे आर्थिक अपराध के मामले- सीएम योगी

लखनऊ।

आर्थिक अपराध के मामलों को तीन माह के भीतर निस्तारित किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को तीन माह से अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और अन्य आर्थिक अपराध न केवल सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास को भी आघात पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है?

नई दिल्ली । बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है?

जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल

क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है? उन्होंने दावा किया कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि राय मंत्रिमंडल ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये निकालने की स्वीकृति दी है। तेजस्वी ने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा अथवा वित्तीय विपत्ति के समय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान प्रभावित

उन्होंने आरोप लगाया, जिस प्रदेश में पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग होने लगे, वहां की स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। पिछले छह

महीनों से हम लगातार कह रहे हैं और यह रिकॉर्डेड भी है कि चार-पांच महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधी भुगतान प्रभावित है, क्योंकि सरकारी खजाना खाली है। राजद नेता ने दावा किया कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप

उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं की बात तो दूर, वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कई कार्यों का अभी तक क्रियान्वयन शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली आपूर्ति में कटौती की जा रही है, छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप पड़ी है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि धन की कमी के कारण राय सरकार ने बिहार राय फसल सहायता योजना को बंद करने का निर्णय लिया है।

वित्तीय स्थिति चिंताजनक

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और नियमित बजटीय प्रावधानों के बजाय आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपये निकालकर पेंशन भुगतान करने जैसे निर्णय पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि दशकों से डबल इंजन सरकार होने के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि नीतीशिए मुख्यमंत्री को गैर-जरूरी मुद्दों को हवा देने के बजाय राय की वित्तीय स्थिति पर बिहारवासियों को संबोधित करना चाहिए और उनकी आशंकाओं को दूर करना चाहिए।